

M/s Deesons Engineers Company v. M/s C. P. Engineering Company
(Koshal, J)

अपीलीय सिविल

ए. डी. कोशल के समक्ष, न्यायमूर्ति

मैसर्स डीसंस इंजीनियर्स कंपनी, अपीलकर्ता

बनाम

मैसर्स सीपी इंजीनियरिंग कंपनी, - उत्तरदाता।

1971 के आदेश संख्या 258 से प्रथम अपील

12 मई, 1972।

माध्यस्थम् अधिनियम (1940 का 10)-धारा 19 और 20-न्यायालय द्वारा किसी अन्य निर्देश के बिना किसी अधिनिर्णय को अपास्त करना- मध्यस्थता का संदर्भ-क्या जीवित रहता है-धारा 20 के तहत आवेदन-क्या किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के अध्याय III में ऐसे मामलों में माध्यस्थम् की परिकल्पना की गई है जहां विवाद के पक्षकार पहले से ही वाद के माध्यम से न्यायालय में नहीं हैं। धारा 20 की उपधारा (1) में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह मध्यस्थता समझौतों पर लागू होती है जहां उसका विषय किसी वाद के माध्यम से न्यायालय में नहीं ले जाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 20 के अधीन कोई आवेदन वर्जित नहीं है, जहां उस न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, जिस पर यह किया गया है, ऐसे आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषय के संबंध में लंबित है। न्यायालय द्वारा 'आगे किसी निर्देश के बिना' किसी अधिनिर्णय को अपास्त किए जाने का तथ्य धारा 20 के अधीन आवेदन किए जाने के मार्ग में बाधक नहीं है। किसी अधिनिर्णय को अपास्त करने का आदेश देते समय, न्यायालय को अधिनियम की धारा 19 के अधीन निर्देश को अपदस्थ करने या न करने का विवेकाधिकार है और यदि न्यायालय निर्देश को अपदस्थ न करने का बाद का मार्ग चुनता है, तो इसे जीवित छोड़ दिया जाता है और अधिनियम की धारा 20 के अधीन आवेदन वर्जित नहीं है।

(Paras 6 and 7)

श्री के. डी. मोहन, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, चंडीगढ़, दिनांक 4 जून, 1971 के न्यायालय के आदेश से पहली अपील, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि चूंकि पुरस्कार को माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी और निर्देश के रद्द कर दिया गया है; कोई लंबित कार्यवाही नहीं है और इसलिए, आवेदकों के दूसरे और तीसरे आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और परिस्थितियों में, आवेदकों के तीन आवेदनों में से किसी पर भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है जो दायर किए जाएंगे। ..

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच. एल. सोनी।
नेमो, उत्तरदाता के लिए।

आदेश

कौशल, जे -13 सितंबर, 1967 को, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी, जो दोनों फर्म हैं, ने श्री राम सरूप शर्मा, अधिवक्ता, चंडीगढ़ को उनके खातों में जाने और प्रत्यर्थी से अपीलार्थी को देय राशि निर्धारित करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। श्री शर्मा ने 6 फरवरी, 1968 को यह घोषणा करते हुए अपना पुरस्कार प्रदान किया कि प्रत्यर्थी से अपीलार्थी को 42,224.22 रुपये की राशि देय थी। पुरस्कार ने प्रत्यर्थी को अपीलार्थी की लागत 228 रुपये के लिए भी उत्तरदायी बनाया।

(2) 22 फरवरी, 1968 को अपीलार्थी ने माध्यस्थम अधिनियम, 1940 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 (2) 17 और 31 (4) के अधीन वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय में आवेदन किया और माध्यस्थम को न्यायालय में उक्त अधिनिर्णय दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। 1 जनवरी, 1970 को विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने आवेदन स्वीकार कर लिया और पुरस्कार को न्यायालय का नियम बना दिया। प्रत्यर्थी फर्म ने तब इस न्यायालय में एक अपील की स्थापना की, जिसे न्यायमूर्ति तुली द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ ने निष्पक्ष, न्यायसंगत या निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया था और पक्षों के खातों को देखे बिना जल्दबाजी में अपना निर्णय दिया था, और निष्कर्ष निकाला: "ऊपर दिए गए कारणों के लिए, यह अपील स्वीकार की जाती है और मध्यस्थ के निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, परिस्थितियों में। मैं पार्टियों को उनका खर्च उठाने के लिए छोड़ देता हूँ "

M/s Deesons Engineers Company v. M/s C. P. Engineering Company
(Koshal, J)

(3) 28 अगस्त, 1970 को, अपीलार्थी ने विद्वत वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश को एक अन्य आवेदन किया, जिसके सुसंगत पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

1 कि अधिनिर्णय किए जाने के विरुद्ध अपील करने पर न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा ने 11 अगस्त, 1970 के आदेश और निर्णय द्वारा अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया।

4 कि उपर्युक्त उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव यह है कि निर्देश पर मध्यस्थ द्वारा पुनः निर्णय लिया जाना है और कानून के अनुसार एक नया निर्णय दिया जाना है।

5 कि मूल माध्यस्थम् करार और पक्षकारों के बीच विवाद के विषय से संबंधित अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ 1968 के मामले संख्या 1 की फाइल पर हैं और उक्त फाइल माननीय न्यायालय में उपलब्ध है।

6 कि मध्यस्थ को संदर्भ के निर्णय के साथ नए सिरे से आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तुत करने और मध्यस्थता समझौते से संबंधित उपर्युक्त रिकॉर्ड मध्यस्थ को भेजा जाए।

* * * * *

8 कि मध्यस्थ द्वारा विवाद के मामले के निर्णय में देरी के कारण आवेदक को नुकसान होने की संभावना है। अतः मध्यस्थ द्वारा शीघ्र निर्णय को सुगम बनाने के लिए मामले की उपरोक्त फाइल को उसे भेजना न्याय के हित में होगा।

तदनुसार प्रार्थना की। "

4 जून, 1971 के अपने आदेश के आधार पर, जो वर्तमान अपील में आक्षेपित है, विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ आवेदन को खारिज कर दिया: "अब जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी और निर्देश के पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है, तो कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और इसलिए, आवेदकों के दूसरे और तीसरे आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की

जा सकती है। इन परिस्थितियों में, दायर किए जाने वाले आवेदकों के तीन आवेदनों में से किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इन कागजों को अभिलेख कक्ष में भेजा जाएगा।

(4) अधिनियम की धारा 19 और 20 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होनी चाहिए। उन खंडों में कहा गया है:

"19. जहां कोई अधिनिर्णय धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन शून्य हो गया है या अपास्त कर दिया गया है, वहां न्यायालय आदेश द्वारा निर्देश को निरस्त कर सकता है और उस पर आदेश देगा कि निर्दिष्ट अंतर के संबंध में मध्यस्थता करार का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

(20)(1) जहां किसी व्यक्ति ने करार के विषय या उसके किसी भाग के संबंध में कोई वाद संस्थित करने के समक्ष माध्यस्थता करार किया है और जहां कोई मतभेद उत्पन्न हुआ है जिससे करार लागू होता है, वहां वे या उनमें से कोई भी, अध्याय 2 के अधीन कार्यवाही करने के स्थान पर, उस मामले में अधिकारिता वाले न्यायालय को, जिससे करार संबंधित है, आवेदन कर सकता है कि करार न्यायालय में दाखिल किया जाए।

(2) आवेदन लिखित रूप में होगा और वादी या वादी के रूप में इच्छुक या इच्छुक होने का दावा करने वाले एक या अधिक पक्षों के बीच और प्रतिवादी या प्रतिवादी के रूप में शेष के बीच एक मुकदमे के रूप में दर्ज किया जाएगा, यदि आवेदन सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, या, यदि अन्यथा, वादी के रूप में आवेदक और प्रतिवादी के रूप में अन्य पक्षों के बीच।

(3) ऐसा आवेदन किए जाने पर, न्यायालय आवेदकों के अलावा समझौते के सभी पक्षों को इसकी सूचना देने का निर्देश देगा, जिसमें उनसे

M/s Deesons Engineers Company v. M/s C. P. Engineering Company
(Koshal, J)

नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर कारण दिखाने की अपेक्षा की जाएगी कि समझौता क्यों दायर नहीं किया जाना चाहिए।

- (4) जहां कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, वहां न्यायालय समझौते को दायर करने का आदेश देगा और पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को, चाहे समझौते में हो या अन्यथा, या जहां पक्षकार मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकते हैं, न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को निर्देश का आदेश देगा।
- (5) इसके पश्चात् माध्यस्थम् इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार, जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है, आगे बढ़ेगा और उनके द्वारा शासित होगा।

(5) धारा 20 अधिनियम के अध्याय 3 में निहित एकमात्र धारा है जिसका शीर्षक इस प्रकार है:

"एक अदालत के हस्तक्षेप के साथ समर्पण जहां कोई मुकदमा नहीं है।"

(6) शीर्षक इंगित करता है कि अधिनियम के अध्याय III में उन मामलों में मध्यस्थता की परिकल्पना की गई है जहां किसी विवाद के पक्षकार पहले से ही किसी वाद के माध्यम से न्यायालय में नहीं हैं। धारा 20 की उपधारा (1) में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह मध्यस्थता समझौतों पर लागू होती है जहां उसका विषय किसी वाद के माध्यम से न्यायालय में नहीं ले जाया गया है। इसके अलावा, धारा 20 की उपधारा (2) में यह आदेश दिया गया है कि उपधारा (1) के तहत किए गए आवेदन को पक्षकारों के बीच वाद के रूप में क्रमांकित और पंजीकृत किया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 20 के अधीन आवेदन न केवल वहां वर्जित है जहां उस न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, जिसके समक्ष वह किया गया है, लेकिन दूसरी ओर, विचार किया जाता है जहां ऐसा विषय पहले से स्थापित वाद के अंतर्गत नहीं आता है। जब विद्वत वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने, इसलिए, यह मत व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा 28

अगस्त, 1970 को किया गया आवेदन सफल नहीं हो सका क्योंकि इस न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय को अपास्त करने के बाद उसके पास कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी, तो यह त्रुटिपूर्ण था।

(7) पुनः, यह तथ्य कि इस न्यायालय द्वारा "बिना किसी और निर्देश के" अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया गया था, धारा 20 के अधीन आवेदन किए जाने के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता था। उस आदेश को देते समय इस न्यायालय को निर्देश का स्थान लेने या न लेने का विवेकाधिकार था और उसने बाद का मार्ग चुना क्योंकि, पुरस्कार को अपास्त करते हुए, न्यायमूर्ति तुली ने उस निर्देश का स्थान लेने का कोई आदेश नहीं दिया, जिसे इसलिए जीवित छोड़ दिया गया था, ताकि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 20 के तहत आवेदन करने का पूरी तरह से हकदार हो। इस प्रकार अधिनियम की धारा 19 की व्याख्या की जानी चाहिए [फर्म गुलाब राय गिरधारी लाई और अन्य बनाम फर्म बंसी लाई हंसराज (1) जुगगीलाल कमलापत बनाम जनरल फाइबर डीलर्स लिमिटेड (2) में अनुमोदित]।

(1) ए आई आर 1959 पी बी 102

(2) ए आई आर 1962 एस सी 1123

(8) अपीलार्थी द्वारा 28 अगस्त, 1970 को विद्वत वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में किए गए आवेदन में कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम की धारा 20 के तहत किया जा रहा था, लेकिन फिर इसकी सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह ऐसा था। इन परिस्थितियों में, यह विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश का कर्तव्य था कि वह गुण-दोष के आधार पर इसका निर्णय करे और इसे इस आधार पर खारिज न करे कि उसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी और इस न्यायालय ने बिना किसी आगे के निर्देश के पुरस्कार को रद्द कर दिया था।

(9) परिणामस्वरूप अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। विद्वत वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश का आदेश, जहां तक वह 28 अगस्त, 1970 के दिनांकित आवेदन से संबंधित है, अपास्त कर दिया गया है और मामला उसे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि वह उस आवेदन पर गुणदोष के आधार

M/s Deesons Engineers Company v. M/s C. P. Engineering Company
(Koshal, J)

पर विचार करेगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

बी. एस. जी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा